



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 8 जुलाई, 2026

आषाढ़ 17, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या 6/2026/599/तीस-4-2026/30-4010(001)/4-2026

लखनऊ, 8 जुलाई, 2026

अधिसूचना

आदेश

प0आ0-431

चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अत्यंत प्रदूषणकारी पुराने व्यावसायिक यानों को प्रतिस्थापित करने के लिए "परिवर्तन योजना (प्रोग्राम फॉर एक्सेलेरेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटीवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पॉल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशंस)" को मंजूरी दी गई है;

और चूंकि, उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र में पूर्वोक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और यान स्वामियों को अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी नवीन या प्रयुक्त व्यावसायिक यानों को क्रय के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, मोटर यान कर (रोड टैक्स) और रजिस्ट्रीकरण फीस पर छूट प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है। यह रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा (आर वी एस एफ) के माध्यम से भारत स्टेज (बीएस-I, बीएस-II, बीएस-III, और बीएस-IV) उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले पुराने ट्रकों और बसों को स्क्रेपिंग करने और उनके स्थान पर नए बीएस-VI या इलेक्ट्रिक यानों के क्रय को प्रोत्साहित करने के लिए लागू होती है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1997) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र के भीतर आने वाले उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में "परिवर्तन योजना" के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा (आर वी एस एफ) के माध्यम से भारत स्टेज (बीएस-I, बीएस-II, बीएस-III, और बीएस-IV) उत्सर्जन मानकों के अनुरूप पुराने ट्रकों (एल जी वी/एम जी वी/एच जी वी) और बसों (एल पी वी/एम पी वी/एच पी वी) को स्कैप करने और उन्हें नए बीएस-VI या इलेक्ट्रिक यानों से प्रतिस्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कर और फीस से छूट देते हैं, अर्थात:-

(क) पूर्वोक्त योजना के अधीन, नवीन यानों के क्रय पर मोटर यान कर में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी और पूर्व-स्वामित्व (प्रयुक्त) यानों के क्रय पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। दोनों ही मामलों में, मोटर यान कर पर छूट 10 वर्ष की अवधि के लिए विधिमाम्य रहेगी;

(ख) पूर्वोक्त योजना के अधीन क्रय किये गये नवीन यानों के लिए "रजिस्ट्रीकरण फीस" पर पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी;

(ग) उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत बीएस-I, बीएस-II, बीएस-III एवं बीएस-IV उत्सर्जन मानक वाले ट्रकों एवं बसों पर एक वर्ष से अधिक की लंबित दायित्व (कर) को अधित्यजन करने हेतु स्वीकृत किया जाता है। यह अधित्यजन केवल उन यान स्वामियों को अनुज्ञेय होगी, जो पुराने यानों को प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा (आर वी एस एफ) के माध्यम से स्कैप करते हैं और उसके स्थान पर एक नवीन बीएस-VI या इलेक्ट्रिक यान का क्रय करते हैं और उसको रजिस्टर कराते हैं।

2-प्रश्नगत योजना उन्हीं निजी बसों एवं ट्रकों के लिए अनुमत्य है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं एवं आदेशों के अनुरूप अर्ह हों।

आज्ञा से,

अर्चना अग्रवाल,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/2026/599/XXX-4-2026/30-4010(001)/4-2026, dated July 8, 2026:

No. 6/2026/599/XXX-4-2026/30-4010(001)/4-2026

Dated Lucknow, July 8, 2026

WHEREAS with a view to control air pollution and protect the environment in the National Capital Region (Delhi-NCR), the "PARIVARTAN" (Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions) has been approved by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), Government of India, to replace highly polluting old commercial vehicles ;

AND WHEREAS, for effective implementation of the aforesaid scheme in the Uttar Pradesh NCR region and to encourage vehicle owners to purchase relatively less polluting new or used commercial vehicles, a decision has been taken to grant exemptions on motor vehicle tax (road tax) and registration fees. This applies to scrapping old trucks and buses adhering to Bharat Stage (BS-I, BS-II, BS-III, and BS-IV) emission standards through a Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF), and encouraging the purchase of new BS-VI or electric vehicles in their place ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997), the Governor is pleased to exempt tax and fees as detailed below, to encourage the scrapping of old trucks (LGV/MGV/HGV) and buses (LPV/MPV/HPV) conforming to Bharat Stage (BS-I, BS-II, BS-III, and BS-IV) emission standards through a Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) under the " PARIVARTAN" across the 8 districts of Uttar Pradesh falling within the Uttar Pradesh NCR region, and replacing them with new BS-VI or electric vehicles, namely:-

(a) under the aforesaid scheme, a 100 percent exemption on motor vehicle tax shall be provided on the purchase of new vehicles, and a 50 percent exemption shall be provided on the purchase of pre-owned (used) vehicles. In both cases, the exemption on motor vehicle tax shall remain valid for a period of 10 years ;

(b) a complete exemption on the "Registration Fee" is granted for new vehicles purchased under the aforesaid scheme ;

(c) approval is granted to waive the pending tax liability of more than one year on trucks and buses conforming to BS-I, BS-II, BS-III, and BS-IV emission standards registered in the NCR region of Uttar Pradesh. This waiver shall be admissible only to those vehicle owners who scrap their old vehicles through an authorized Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) and purchase and register a new BS-VI or electric vehicle in its place.

2. This Scheme applies only to those private buses and trucks that meet the eligibility criteria specified in the notifications and orders issued by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India.

By order,
ARCHANA AGRAWAL,
Apar Mukhya Sachiv.